

चल रही थी। इलाहाबाद जनपद की बारा, बर-छना तथा भेजा तहसीलों विद्य रेंज में पड़ती हैं जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है तथा जमीन भी समतल बहुत कम है। इन तहसीलों में डी पी ए पी योजना में काफी कार्य हो रहा था किन्तु भारत सरकार से निर्देश हुआ है कि इलाहाबाद जनपद में 21.3.83 से डी पी ए योजना समाप्त कर दी जाए और कर दी गई है।

दुख इस बात का है कि डी पी ए पी योजना के तहत जो कार्य हो रहे थे वे भी अपूर्ण रह गए हैं। यदि उनको पूर्ण न किया गया तो जो धन व्यय हुआ है वह भी व्यर्थ हो जाएगा।

मेरा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके डी पी ए पी योजना को पुनः इलाहाबाद जनपद में चलाने का आदेश दे दें।

### (III) EARLY CONSTRUCTION OF A 'KISAN NIVAS' AT DELHI

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : हमारे देश में सबसे अधिक संख्या किसानों की है। किसान खद्यान्न पैदा करता है। दूध पैदा करता है। कपास पैदा करता है। अपने पुत्र और भाई देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। सर्वाधिक वोट दे कर सरकार बनाता है। सब से अधिक परिश्रम करता है और सब से कम उत्पादन का उपभोग करता है। संसार में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उसी का हाथ है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने का मुख्य कारण कृषि उत्पादन है। यही नहीं, स्वतन्त्रता के आंदोलन में जेल में भी किसान ही अधिक गए। किसान के पुत्र और भाई पुलिस में अधिक हैं। वे ही देश की व्यवस्था बनाए हुए हैं। जब बेचारा किसान किसान कभी दिल्ली आता है तो उसके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। उसके ठहरने के लिए एक विशाल किसान निवास दिल्ली में बनना चाहिये ताकि वह बेचारा आकर ठहर सके। मेरी

केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना है कि किसानों के ठहरने के लिए अविलम्ब एक किसान निवास बनवाएं, जैसा कि मथुरा नगर में बना हुआ है।

### (IV) FINANCIAL ASSISTANCE TO GUJARAT FOR PROPER IMPLEMENTATION OF DRINKING WATER SUPPLY SCHEMES.

SHRI AHMED MOHAMMED PATEL (Broach) : The State Government has undertaken a programme of providing drinking water facilities in problem villages on top priority basis. Out of the total i.e. 9038 problem villages, 3720 villages were provided water supply facilities by 31.3.1980, leaving 5318 villages to be tackled at the beginning of the Sixth Five Year Plan (1980-85).

During the first two years of Sixth Plan i.e. 1980-81 and 1981-82, 1106 villages are covered. This leaves 4212 villages to be tackled within three years (1982-85). The geo-hydrological conditions in Gujarat have been changed. The district or Kutch is an arid region. Banaskatha and part of North and South Gajarat, and all the districts in Saurashtra region are drought prone areas. Also, the State has a long coastal area. This has created the problem of salinity ingress. Underground sub-soil water level is going deep every year. These geological situations have made the water supply problem more difficult.

Considering all these aspects and price escalation, the funds required to tackle remaining 4212 villages work out to Rs. 102.95 crores. Government of India has been requested to increase the allocation of Rs. 52.60 crores to achieve the target of 5318 villages by the end of Sixth Plan (1980-85). The programme of providing drinking water facilities to the problem villages is a part of the new 20- Point Programme, and the State Government is very keen to achieve the target, as planned. This issue, therefore, requires immediate attention of Central Government, so that drinking water facilities can be provided to the problem villages.

### (V) NEED FOR PROPAGATION AND DEVELOPMENT OF THE BAJJIKA LANGUAGE.

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : भगवान बुद्ध के समय से ही बिहार में एक जनपद था जिस का नाम था बज्जि । इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी 'बज्जिका' । आज भी यह भाषा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, सारण क्षेत्रों में लोक भाषा है । इस भाषा के बोलने वाले लगभग एक करोड़ हैं । इस भाषा की एक लिपि भी थी जो ब्रिटिश काल में कचहरी, दस्तावेज एवं पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त होती थी । आज भी इस भाषा में दर्जनों पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित हैं । किन्तु इस भाषा के प्रसार, प्रचार के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में पर्याप्त प्रयासों का सर्वथा अभाव रहा है । यहां तक बिहार की अन्य भाषाओं के समान इस भाषा को स्थान तक नहीं दिया गया । आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि पर भी इस भाषा को स्थान उपलब्ध नहीं है । इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि सरकार इस भाषा के समुचित उत्थान, प्रसार एवं प्रचार की दिशा में अग्रसर हो और प्रसार करे ।

(VI) NEED FOR WIDENING AND RAISING OF TUNNELS CONNECTING NORTHERN AND SOUTHERN SIDES OF ASANSOL.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan) : I would like to bring to the immediate notice of the Government the plight of the people who have to use the two tunnels connecting the northern side of Asansol with the southern. These tunnels are the only link roads for the people of several railway colonies and the inhabitants of Kasai Mohalla, old Kabārsthan and Jhinri Mohalla. The tunnels are almost as ancient as the Indian Railways and were built by the Britishers to extend the railway line from Raniganj to Asansol. Not only are they dilapidated but are so narrow and waterlogged that it is extremely difficult to cross the tunnels, trudging along waist deep mud during the monsoons. The schism between the fast enlarging slums in the outskirts of Asansol because of these waterlogged low lying

tunnels and the Asansol town with modern roads is not only posing problems of law and order but is creating a socially explosive situation. I, would, therefore, request the government to give the matter serious thought. If widening and raising the tunnels is not feasible, construction of a flyover seems to be the only alternative to put an end to the miseries of the people living in the area.

(VII) NEED FOR IMPROVING THE BOT OF GURJAR BAKHARWALAN IN JAMMU AND KASHMIR.

श्री राजेश पाहलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष जी, गुर्जर बखरवालान की स्थिति जम्मू और कश्मीर में बहुत दयनीय है । आर्थिक स्थिति इन लोगों की शुरू से ही खराब है । सरकार ने इनकी मदद के लिये जो भी कदम उठाये हैं वह भी पूरी तरह से इन लोगों तक नहीं पहुंचे हैं । जो पैसा केन्द्र सरकार ने इन लोगों के होस्टलों आदि में खर्च करने के लिये दिया था उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया । यहां तक कि जो बच्चे होस्टलों में रहते हैं उन बच्चों को मिलने वाली पूरी सुविधा नहीं दी गई ।

इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय भेड़ और बकरी चरा कर गुजारा करना है । अब तक न तो केन्द्र सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और न ही राज्य सरकार ने । जो केन्द्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है वह इस राज्य में लागू नहीं किया । इसके कारण यह लोग भूखे मर रहे हैं । मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि इसमें केन्द्र सरकार दखल दे । इस विषय में केन्द्र सरकार जल्दी कदम उठाये । यह वह बहादुर लोग हैं जिन्होंने देश के लिये 1965 व 1971 की लड़ाई में एक साधारण नागरिक होते हुए भी एक फौजी का रोल अदा किया । कई लोगों को सरकार ने बहादुरी के पुरस्कार दिये । इन सब चीजों के बावजूद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । यह लोग देश के बार्डर पर हैं । वहां पर हमारे देश की नाजुक स्थिति रहती है । इनमें विश्वास कायम रखने के